Government's statements for raids on training camps for Kashmiri terrorists in Pak-occupied Kashmir

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया ... **(व्यवधान)** ।

उपसभापति : यह आपका हाउस के सामने मैडन भाषण है । ?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदया, मैं नया सदस्य हूं और पहली बार कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

उपसभापति : हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे ।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं अपने उल्लेख विशेष से सदन का ध्यान कश्मीर और पंजाब में उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले मैं आज की सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उसने अत्यन्त साहसपूर्ण स्पष्ट शब्दों में और एक सही दिशा में पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अपनी नीति स्पष्ट की है ।

अगर इस किस्म की नीति पहले अपनाई गई होती तो पाकिस्तान को इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होती। वैसे पाकिस्तान द्वारा संधियों और समझौतों की अवहेलना और विश्वासघात करने का बहुत लंबा इतिहास रहा है । 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 1948–1949 को राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की अवहेलना शिमला समझौते की अवहेलना, जो 1972 में हुआ था, और इसके अलावा कई बार प्रधान मंत्रियों में और दोनों देशों की सरकारों में आपस में जो बातचीत हुई है उसकी भी पालना पाकिस्तान ने नहीं की है । पाकिस्तान के बारे में आज भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री ने, हमारी सरकार के प्रवक्ता ने, गृह मंत्री ने कुछ बातें स्पष्ट की हैं । मुझे लगता है कि जो कुछ अभी हाल में न्यूयार्क में हुआ है, दोनों विदेश मंत्रियों की आपस में जो चर्चा हुई, उससे यह लगा कि शायद दोनों देश किसी आपसी तालमेल के बारे में फिर से इस पर विचार करने के लिए तैयार हो जायेंगे । यह बात 25 अप्रैल की हुई । लेकिन 26 अप्रैल को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया जिसका अर्थ यह था कि जो एक दिन पहले बातचीत हुई थी वह उस पर भी कायम नहीं रहे। पाकिस्तान हमारे देश के प्रति अमित्रतापूर्ण और शत्रुतापूर्ण भाव लेकर कितनी ही किस्म की कार्यवाहियां कर रहा है । खासतौर पर पिछले दस वर्षों में कश्मीर में और पंजाब में आतंकवादियों और अलगाववादियों को पाकिस्तान द्वारा शस्त्र भेजा जाना तथा पाकिस्तान द्वारा घुसपैठिए भेजे जाना, ये सब घटनायें अब कोई छुपी हुई नहीं हैं । अब तो यह तक हो गया कि पाकिस्तान की प्रधान मंत्री, श्रीमती बेनजीर भुट्टो और अन्य नेताओं ने खुलेआम यह स्वीकार किया है कि हम पैसा भेज रहे हैं कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है वही नहीं बल्कि कश्मीर का जो हिस्सा भारत में है, उसको आजाद कराने के लिए हम सब किस्म के पग उठाना चाहते हैं । यह जो उन्होंने बातें कहीं हैं इसके साथ ही उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि कश्मीर के अंदर भारत सरकार बहुत अन्याय और अत्याचार कर रही है । मैं पाकिस्तान को स्मरण कराना चाहता हूं कि 1973 में पाकिस्तान ने बलुचिस्तान पर, अपने ही क्षेत्र में बमबारमेंट किया था जिसमें तीन हजार नागरिक मारे गये थे । ऐसा देश अगर कश्मीर के बारे में, जहां पर हमारी सरकार नियमों के अनुसार, विधान के अनुसार अपने प्रशासन के अन्तर्गत रहते हुए वहां की परिस्थिति को ठीक तरह से निपटाने के लिए कुछ कार्यवाही कर रही है तो उस पर आपत्ति करने का उसको कोई अधिकार नहीं है । एक बात जो अब कही गई है वह पहले कही जानी चाहिए थी और वह यह है कि पाकिस्तान जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों को भेज रहा है, उन क्षेत्रों पर हमला करके उनको नष्ट करने का हमको अधिकार है । यह जब मैं कह रहा हूं तो मैं पाकिस्तान के क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं । हमें यह समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वह युद्ध विराम रेखा जो 1947 में लागू हुई उसके कारण है और 1948–49 में जो यू०एन०ओ० का रेजूल्यूशन था, जिसको पाकिस्तान

ने नहीं माना और इसके कारण वह क्षेत्र अभी तक पाकिस्तान के पास है। यह क्षेत्र भारत का है। हमारा उस पर सब प्रकार से अधिकार है। हमारे क्षेत्र में ही बैठकर वह हमारे कश्मीर पर आक्रमण की बातें करें, वहां घुसपैठिये भेजे यह हमें बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन जब कर दिया तो अब केवल एक बात रह गई है कि भारत यह तय करे कि युद्ध-विराम रेखा का जो उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है उसका उत्तर कैसे दे और कब दें। जो सीज फायर लाइन है, उसके अंदर अगर कैंप चलेंगे, आतंकवादियों का प्रशिक्षण होगा और उन लोगों को इस देश में भेजा जायेगा तो उनको नष्ट करने का हमें पूरा अधिकार है, मैं प्रधान मंत्री के इस सुझाव का भी स्वागत करता हूं कि पाकिस्तान से जब यह संकेत मिल रहे हैं कि उसने परमाणु बम बनाया है तो भारत भी अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए परमाणु बम बनाने के बारे में निर्णय ले सकता है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस संबंध में पाकिस्तान की प्रतीक्षा न करें। उसकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए भारत अपने इस निर्णय की, अपनी इस नीति की स्पष्ट घोषणा करे कि भारत भी परमाणु बम बनायेगा। हमें किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहिए ताकि युद्ध के समय पाकिस्तान इस भ्रम में न रहे कि उसे किसी तरह से सैनिक वरीयता प्राप्त है।

हमारे इस देश के अंदर सब लोग, सारे देश के लोग, अब यह अलग बात है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, देश के ऊपर यह संकट के विषय पर एक हैं, इसमें कोई बायें बैठते या दायें बैठते इसका कोई सवाल नहीं है। यह भी सवाल नहीं है कि हम यह समझें कि एक सरकार है वह अगर देश की एकता और अखंडता के बारे में कोई काम करना चाहती है तो केवल उसको चिन्ता कर शोर मचा कर रोकने के लिए या उसका ध्यान दूसरी तरफ़ खींचने के लिए या केवल कि दलगत बातों को ले कर हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को पीछे डाल दें तो यह अच्छा नहीं होगा। आज सारे राष्ट्र का संकल्प है हम देश की एकता और अखंडता के लिए सब साथ हैं, सब एक हैं,। आज हमें पाकिस्तान को यह बताना होगा कि यह जो कुछ भी हमारी सरकार ने घोषणायें की हैं कि हम उनके प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर सकते हैं, सारा देश इसके पीछे हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि परमाणु बम बनाने की नीति अगर सरकार अपनाएगी तो हम उसके साथ हैं। कोई भी कदम कड़ाई के साथ जो यह सरकार उठाएगी, हम उसके साथ हैं। एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। जहां हमें पाकिस्तान को दो टूक बात कहनी है, सख्ती से जवाब देना है, वह हमें यह भी साफ़ कर देना है कि हमारे देश के किसी भी हिस्से में चाहे वह पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो वहां के जितने भी लोग हैं जो विदेशों में बैठकर हमारे खिलाफ़ षडयंत्र कर रहे हैं, हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि उन सब लोगों को वापिस बुलायें, वहां की सरकारों को बाध्य करें कि वह सब लोग हमें सौंपे जाएं। इस समय पंजाब की दोनों पंथक कमेटियों के जो सरगना हैं, नेता हैं, वह पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां से षडयंत्र कर रहे हैं हमें पाकिस्तान को यह कहना है कि वह इन लोगों को हमें सौंपे। अमानुल्ला खान के बारे में सरकार कार्यवाही करने की कोशिश कर रही है। यह कार्यवाही किस तरह से हो सकती है, वह भी करे। देश के अन्दर जितने आतंकवादी और अलगाववादी हैं हमारी सरकार ने संकल्प भी किया है कि उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनके साथ, उनके वकीलों के साथ जो उनकी वकालत करते हैं या ऐसे काम करते हैं उन के साथ कोई बात न हो। अंत में, मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि परमाणु बम की नीति के बारे में और हमारे जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास हैं, जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन कर दिया है तो हमें इस संबंध में स्पष्ट कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद।

उपसभापति : शर्मा जी, आप का यह पहला स्पेशल मेंशन था इसलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम अलाऊ कर दिया।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मुझे थोड़ा साहस हुआ क्योंकि अभी एक अन्य स्पेशल

मेंशन पर आधा घन्टे से ज्यादा समय लगा है। मुझे लगता है शायद इस तरह से कुछ पुराने सदस्यों को ही आप अलाऊ करती हैं।

श्री पी० शिवशंकर (गुजरात) : आपका यह मेंडन स्पीच है, इसलिये ज्यादा टाइम अलाऊ किया है।

उपसभापति : आपका मेडेन स्पीच है इसलिए ज्यादा टाइम अलाऊ किया है। जो पहले वाला स्पेशल मेंशन था वह हरिजनों के बारे में था और उस पर कुछ गर्मागर्मी भी हुई इसलिए उस पर ज्यादा टाइम दिया गया। कृपा कर के आइंदा एक सीमा में रखिएगा नहीं तो आपको स्पेशल मेंशन देने में थोडी हिचकिचाहट होगी। जहां तक देश की एकता और अखण्डता का सवाल है, उस में पूरा हाउस और चेअर भी आपके साथ है।

Communal riots in Kanpur

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, कानपुर में पिछले दिनों जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ था, उस संदर्भ में विशेष उल्लेख करने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी की जन्म भूमि है और सन् 1931 ईस्वी में जब स्वतंत्रता संग्राम में उनकी हत्या की गई उस समय कानपुर में दंगे की आग भड़की थी। उसके बाद जब हमारी अवतारी शक्ति देवी इंदिरा जी का बलिदान हुआ। उस समय दंगे की आग भड़की थी उसके बाद कानपुर एकदम शांत रहा और आपस में भाईचारे के साथ, हिंदू मुसलमानों में एकता के साथ रह रहा था। उसके बाद पिछली 18 अप्रल की शाम को साढ़ 7 बजे दो व्यक्तियों में—एक मोटर साइकिल पर था और एक साइकिल पर—कुछ कहा सुनी हुई और दोनों ने मामले को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की। कहा जाता है कि माफ़िया गिरोह का यह आपसी झगडा है, कुछ लोग मकानों पर कब्जा करते हैं और उन्हें निकालते हैं, कुछ लोग जुए के अड्डे चलाते हैं और उसके शेयर बांटने का झगडा है, कुछ लोग इसी तरह से तस्करी आदि का काम करते हैं इनके जो दो गैंग हैं इनका यह झगड़ा बताया गया। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर उत्तर प्रदेश का शासन और कानपुर का प्रशासन उदासीन रहा, जिस तरह से प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी और इस दंगे को साम्प्रदायिक रंग भरने का मौका दिया यह बड़ी ही चिंता की बात है। 5 व्यक्तियों की हत्या हुई और पाकिस्तनी के बने हुए बहुत से अस्त्र शस्त्र वहां बरामद हुए। पहले ही कहा जा चुका है कि पाकिस्तान से कानपुर में नाजाइज ढंग से हथियार आ रहे हैं। इस दंगे के दरम्यान जो रेड किए गए, जो छापे मारे गए उनमें पाकिस्तान के बने हुए कितने हथियार मिले हैं यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं। हमारे दल के सांसद श्री अहलुवालिया और हमारे राजस्थान के एक दूसरे सांसद वहां गए थे और वहां पर उन्होंने लोगों से मिल करके इस साम्प्रदायिक आग को बुझाने की कोशिश की परन्तु वहां के प्रशासन ने उनका कोई साथ नहीं दिया। दूसरे सांसद श्री अबरार अहमद जी थे। पी० ए० सी० की गोलियों से वहां कई मुसलमान मारे गए और उस समय वहां का प्रशासन बजरंग दल को धर्म जागरण यात्रा की अनुमति दे रहा था जबकि मुसलमानों का त्योहार भी सिर पर था। एक तरह से साम्प्रदायिकता को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि जितने भी साम्प्रदायिक दल हैं चाहे वे हिन्दुओं के हों, मुसलमानों के हों, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, जमायते इस्लामी हो इन्हें बन्द किया जाए। परन्तु सरकार जानबूझकर ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों के हाथ में खेल रही है जो केवल अपना हितचिंतन करने के लिए इस देश के निर्दोष लोगों में हिन्दू-मुसलमान की भावना जागृत करके खून बहाना चाहते हैं और इस बजरंग दल के प्रोसेशन में माननीय उपसभापति जी "कटी सुपारी, हरा पान, कटुआ भागों पाकिस्तान" जैसे घिनोने नारे लगे। इतना ही नहीं "इस देश में हिंदू 60 करोड, दंगे मजिस्द सारी तोड" तथा यह भी नारे लगे कि हम मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवायेंगे मस्जिद को तोडकर, काशी में विश्वनाथ मंदिर बनायेंगे मस्जिद को तोड़कर और राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनायेंगे लेकिन यह प्रशासन सोता रहा। मुख्य मंत्री ने 21